

प्रेषक,

एस0के0 मुट्ठू,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 04 जून, 2010

विषय:- एडुकोम्प इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं स्कूल मैनेजमेन्ट लि0 नई दिल्ली को ग्राम गिरध्वामुंशी, तहसील जसपुर, जिला उधमसिंहनगर में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 2.76 एकड़ भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-220/सात-स0भू0अ0/2009, दिनांक 14.8.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, एडुकोम्प इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं स्कूल मैनेजमेन्ट लि0 नई दिल्ली को ग्राम गिरध्वामुंशी, तहसील जसपुर, जिला उधमसिंहनगर में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 2.76 एकड़ भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खसरा संख्या के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय हेतु) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- प्रस्तावित भूमि का उपयोग, संस्था द्वारा मात्र शैक्षणिक कार्यों हेतु ही किया जाएगा तथा इससे भिन्न कार्यों हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है, तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जाएगी एवं संस्था के विरुद्ध, विविध कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

8- संस्था द्वारा संबंधित विभागों, यथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फायर सर्विस आदि विभागों से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही भूमि का उपयोग किया जाएगा।

9- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो। इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाए।

10- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

12- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

13- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किए जाने वाले आदेश की प्रति, यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(एस0के0मुट्टू)

प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०— 1244 / सम्दिनांकित / 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4— एडुकोम्प इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं स्कूल मैनेजमेन्ट लि०, पंजीकृत कार्यालय, 1211 पदमा टावर—1,5 राजेन्द्रा पैलेस, नई दिल्ली।
- 5— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय ✓
- 6— प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।